1	2	3
27	Dadra & Nagar Haveli	Nil
28	Goa, Daman and Diu	66
29	Lakshadweep	Nil
30	Mizoram	214
31	Pondicherry	118
	TOTAL	2,30,784

Violence in Semi Finals between Korea and Kuwait

228. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE:

SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY:

Will the Minister of SPORTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during the ASIAD-Asian Games-Violence in the semi-finals between Korea and Kuwait resulted in the assault on the Thai refree;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what was the role of the Tibetan Border Police;

(d) whether their presence was summoned by the Asian Games Authorities—(of the Tibetan Border Police); and

(e) whether the Koreans have complained to the Asian Games Authorities for excess committed by the Tibetan Border Police?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) Immediately after the semi-final footbal match between Kuwait and Korea, some pesons assaulted the Thai referee. However, the situation was saved by the intervention of the Security staff posted in the Stadium.

(c) The role of the Indo-Tibetan Border Police was to assist the Delhi Police who were responsible for security during the IX Asian Games.

(d) No, Sir,

(e) No, Sir.

सरकारी चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को दिये गये गन्ने के मूल्य

229. श्री अशफाक हुसैन : क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन चल रहे चीनी मिलों के नाम क्या है ;

(ख) इन मिलों द्वारा तथा निजी क्षेत्र के अन्य मिलों द्वारा एवम राज्य सरकार के अधीन चल रहे मिलों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को गन्ने का प्रति क्विंटल क्या-क्या मूल्य दिया गया ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन चल रहे चीनी मिल में पृथक्-पृथक् मूल्य ढांचा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय तत्सम्बन्धी स्थिति क्या है ;

(ङ) क्या इन मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों को भी राज्य सरकार द्वारा आरम्भ से ही निश्चित किये गये मूल्य अदा किये जायेंगे; और

(च) क्या इस तरह का कोई आश्वासन सरकार तथा कस्टोडियन द्वारा दिया गया है ?

खाद्य तथा नागरिक पुर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत आजाद) : (क) उपाबन्ध–I के रूप में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5798/83]

(ख) उपाबन्ध–II से II के रूप में विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5798/83]

(ग) जी हां । केवल 1982–83 मौसम के लिए ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन मिलों के अभिरक्षकों को परामर्श दिया गया था कि वे वही मूल्य अदा करें जो कि आर्थिक रूप से लाभकारी समझे जाते हों । केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए मूल्य बराबर अदा किए जा रहे हैं ।

(ङ) इस समय राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों को अदा करने विषयक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(च) जी नहीं ।

ग्रामीण विकास के लिए राजस्थान को नियतन

230 **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को 1982–83 के दौरान ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कितनी धनराशि नियत की है; और

(ख) जालौर जिले के पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा सिरोही जिले के आदिवासियों के उत्थान के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) वर्ष 1982–83 के दौरान ग्रामीण विकास के कुछ मुख्य कार्यक्रमों अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए राजस्थान को दिए गए निधियों के केन्द्रीय आवंटन का संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

(ख) इस प्रकार की जिला-वार सूचना इस मंत्रालय में एकत्र नहीं की जाती है ।

वर्ष 1982-83 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान को दिए गए केन्द्रीय आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

कार्यक्रम	निधियों का केन्द्रीय आवंटन
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	928.00
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	492.00
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र - कार्यक्रम	290.00
4. मरूभूमि विकास कार्यक्रम	785.50